

प्रेषक,

सी० एस० नपलच्याल,  
सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्री विजय बहुगुणा,  
मा० पूर्व मुख्यमंत्री,  
उत्तराखण्ड।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2

दिनांक : 1 फरवरी, 2017।

विषय :- आवंटित शासकीय आवास के अध्यारोपित अतिरिक्त किराये के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सम्पत्ति अनु-02 के पूर्व प्रेषित नोटिस सं०-1333/xxxii-2-2016-3(31)/2015, दि० 17, अक्टूबर, 2016 एवं सं०-1476/xxxii-2-2016-3(31)/2015, दि० 29, नवम्बर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको आवंटित शासकीय आवास को दि० 16, दिसम्बर, 2016 तक रिक्त करने तथा आवास के अध्यारोपित किराये की आगणित राशि रू० 39,440.00 का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया था।

2- उक्तानुसार किये गये अनुरोध के क्रम में आपके द्वारा आवंटित आवास के अध्यारोपित किराये की आगणित राशि रू० 39,440.00 का भुगतान कर दिया गया है, किन्तु उक्त आवास को आतिथि तक रिक्त नहीं किया गया है। मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञानित कराया गया है कि आपके द्वारा मा० न्यायालय में प्रस्तुत अनुबंध के अनुसार उक्त आवंटित आवास को दि० 15, फरवरी, 2017 तक रिक्त करने हेतु शपथ पत्र दिया गया है।

3- उपरोक्त के आलोक में आपको आवंटित आवास के दि० 31, अक्टूबर, 2016 तक का आगणित किराया रू० 39,440.00 था, जो आपके द्वारा मा० न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र के क्रम में दि० 01, नवम्बर, 2016 से 15, फरवरी, 2017 तक की कुल अवधि 03 माह, 15 दिन का नियमावली के अनुसार रू० 4,200.00 ( 03 माह, 15 दिन × रू० 1200.00 ) अतिरिक्त अध्यारोपित होता है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्तानुसार आगणित अतिरिक्त किराये रू० 4,200.00 की राशि का भुगतान मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग को करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( सी० एस० नपलच्याल )

सचिव।

संख्या: 174/xxxii-2-2017-3(31)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन/मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल/ गोपन(मंत्रिपरिषद्) विभाग/सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, विधानसभा सचिवालय, /सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड/निजी सचिव, मा० मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मा० अध्यक्ष, विधानसभा, उत्तराखण्ड/निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन/राज्य सम्पत्ति अनु-01 एवं 03/एन०आई०सी०, देहरादून/गार्डफाइल।
- 4- मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अध्यारोपित अतिरिक्त किराये की राशि को प्राप्त करते हुए, नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

( विनय शंकर पाण्डेय )

अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी